leading to a lot of repercussions. Madam, I visited Madhya Pradesh and Rajasthan as a member of the Narcotics Committee. Of course, it is used for medicinal purposes, but since they get more than the required quantity they are smuggling it to Bangladesh, Burma and to other places. It is being taken to other countries and it comes back to India after refining. By that our children are being spoiled. Their life is in peril. Therefore, I say that this G.O. will lead to undesirable consequences. That would enable the cultivators to sell it in the black market. It is being sold at Rs. 6,000 or Rs. 7,000 per kilogram. People from Pakistan also come through illegal routes and purchase it. Therefore, I demand that an inquiry be ordered by the Prime Minister. The CBI should enquire why such an order has been passed, when the Committee had recommended that the poppy cultivation in India should be banned.

**Countrywide protests by students demanding reservation for women representatives in parliament and Legislatures**

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Madam, a large number of students, including members of the Students' Federation of India, have demonstrated countrywide on 18th of this month against delaying and postponing of the Women's Reservation Bill supposed to be passed during this session of Parliament.

At the penultimate hour of the winter session of Parliament. I am constrained to say that those who conspired to postpone this important and burning issue on the national agenda have been successful to a great extent. I am raising this issue because there has been a countrywide demonstration by students here. There is a scope for complacency. There is an angularity of certain people viewing this as a welfare programme or as a welfare scheme for women. It need not be repeated. It is not anything like that. There are many problems involving women. According to a news report, the Gender Study Group of the Delhi School of Economics have submitted their latest sample survey wherein they say that 85 per cent of the girls studying in the Delhi University are subjected to physical form of sexual harassment. There are many incidents of atrocities against women, exploitation of women at their working places and hidden form of exploitation and many other forms of exploitation.

My intention to raise this issue is if none of these problems is solved, if none of these problems is attended to, the atrocities against women would continue. Unless the basic issue, the fundamental question, that is, the empowerment of women which is a burning issue on the national agenda is taken up, the atrocities against women cannot be checked. Thank you.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I associate myself with the Special Mention made by my colleague.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, we also lend our support to the Special Mention made by the hon. Member.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think all of us should associate ourselves with the Special Mention made by the hon. Member.

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय** (पश्चिम बंगाल): महोदय, मेरा नाम है। मैं आधा मिनट बोलूंगी।

**उपसभापति:** बोलिए।

**श्रीमती चन्द्रकला पांडेय:** महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया।

महोदया, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शायद मैं अंतिम वक्ता हूं। मैं बड़े खेद और दुख के साथ अपनी और देश की हजारों-करोड़ों महिलाओं की आवाज आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में आकर हमें एक आशा और उम्मीद की किरण दिखाई थी। मलयालम में एक कहावत है कि यदि देना है तो दो, सपने न दो। जब उन्हें नहीं देना था तो नहीं देते लेकिन उन्होंने यह सपना दिखाकर, वे 30 दिनों तक हमें आशा की किरण दिखाते रहे कि आज नहीं तो कल मंत्री जी बिल लेकर आयेंगे। लेकनि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि महिलाओं को

कुछ न देने के लिए यह एक साजिश है। शायद अभी भी देश के कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि महिलायें केवल काफी बनायें, चाय बनायें या दाई और धाय ही बनी रहें। मैं आपके माध्यम से यह आशा व्यक्त करना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री जी तक यह बात पहुंचा दें कि वे आगामी सत्र में यह बिल यहां पेश करके पास करा दें।

**श्रीमती रेणुका चौधरी** (आन्ध्र प्रदेश): अब हम देने के लिए नहीं कह रहे हैं। आइंदा हम लेंगे। कोई पूछने की जरूरत नहीं है।

**Need to bring back the Snow and Avalanche Study Establishment in Himachal Pradesh**

**श्री महेश्वर सिंह** (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से और इस विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रतिरक्षा मंत्री के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहूंगा। महोदया, जैसा आपको विदित ही है कि 1962 में चाइनीज एग्रेशन के उपरान्त सेना की टुकड़ियों को भारी संख्या में लेह और लद्दाख के बार्डर पर भेजा गया था। उसके उपरान्त हिमखंड और हिमस्खलन होने से कई नौजवान मारे गए थे। इस के लिए यह आवश्यक समझा गया था कि कोई ऐसी संस्था स्थापित की जाए जो इन हिमखंडों का अध्ययन करे और वह ऐसे हिमखंडों के गिरने की पूर्व सूचना दे सके ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से 1969 में मनाली के बांग नामक स्थान पर "सासे" नामक संस्था की स्थापना की गई, स्नो एंड एवलांश स्टडी एस्टेबिलशमेंट, इस संस्था की स्थापना की गई और लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली और यह बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। पूर्व सूचना मिलने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों समें शिफ्ट कर दिया जाता है और कीमती जानों को बचाया जाता है। महोदया, लेकिन यह खेद का विषय है कि जब से इस संस्थान की स्थापना हुई तब से लेकर कुछ अधिकारी लोग अपने स्वार्थ के कारण इस संस्था को वहां से चंडीगढ़ और दूसरे क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करते रहे हैं। 1991 में भी उन्होंने इस प्रकार की कोशिश की लेकिन उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री श्री शरद पवार के ध्यान में हम लोग यह बात लाये और उन्होंने स्थगन आदेश दे दिया और वह दफ्तर वहां चलता रहा। लेकिन गत वर्ष जब दरिया व्यास में बाढ़ आई और उस संस्थान में कुछ नुकसान हुआ तो वहां के उन अधिकारियों को यह एक हथियार मिल गया और जब इसकी आड़ में उन्होंने पुनः जोर डालना शुरू कर दिया है कि यह संस्थान वहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। और अंततोगत्वा वे इस षडयंत्र में सफल हो गए। मैं एक पत्र आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। यह पत्र डायरेक्टर आफ परसोनल जो यहां पर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के हैं, प्रतिरक्षा मंत्रालय में, उन्होंने वहां के डायरेक्टर को लिखा, कि, जैसा कि आपने 1991 में चाहा था और अब आपने पुनः उसकी अनुशंसा की है आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस दफ्तर को हरियाणा के रामगढ़ नामक स्थान में पंचकुला ले जाया जाए। महोदया, इस बात को लेकर लोगों में बहुत रोष है। बहुत सुनियोजित ढंग से एक के बाद एक वहां से दफ्तर हटा रहे हैं। आप भी मेरे सहमत होंगी महोदया कि जैसा कि इस दफ्तर का नाम है स्नो एण्ड एवेलांश स्टडी, तो जब वहां बर्फ ही नहीं पड़ती है फिर वे किसकी स्टडी करेंगे। क्या सारे के सारे उस क्षेत्र में ऐसा खतरा पैदा हो गया है कि जिन लोगों की रक्षा के लिए जिस संस्थान की स्थापना की गयी थी वह वहां से पलायन करके भाग जाए, तो फिर कुल्लू जिले में रहने वाले लोगों और जो हमारे देश की सीमा पर प्रहरी लोग हैं उनका क्या होगा। उनको वार्निंग देने के लिए ही, पूर्व सूचना देने के लिए ही इस संस्थान की स्थापना वहां की गयी थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रतिरक्षा मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि कुल्लू में जगह उपलब्ध है। यह शार्टेस्ट रूट है लेह लद्दाख के लिए इसलिए आर्मी की जितनी सप्लाई जाती है चंडीगढ़ से वह कुल्लू मनाली होकर जाती है। वह उपुक्त स्थान है। अब तो वहां दरिया ने फिर अपना कोर्स बदल दिया है। इसलिए वहां पर यह कार्यालय रहना चाहिए और जिस कार्य के लिए इस संस्था की स्थापना की गयी थी वह कार्य वहां होना चाहिए।

आपने मुझे अंतिम दिन में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

**उपसभापतिः** अंतिम दिन "भी दिया"। "ही नहीं दिया", "भी दिया"।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, I am very grateful to you for conducting the House in a nice way. The House is very grateful to you. You controlled all of us in a talented way, though we are a little vigorous sometimes. Thank you very much

**श्रीमती कमला सिन्हा** (बिहार): मैडम,...

**उपसभापतिः** पहले मैं बोल दूं। फिर आप लोग मेरा शुक्रिया अदा कर दें।